(c) whether it is also a fact that CAG has also pointed out that NCCF, has not, so far, fixed responsibility in the case of export of wheat bran where concerned officer failed to invoke Bank Guarantee of Rs. 2 lakhs within its validity period;

(d) if so, what action has been taken against the involved Deputy Manager; and

(e) what are the reasons for merely transfering the said officer to another branch within the same station?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) The Comptroller and Auditor General of India in his report on NCCF for the year ended 31-3-1987 has pointed out irregularities in certain import|export deals. However, all these deals were not initiated by the then Deputy Manager (Imports).

(b) The Deputy Manager (Imports) is one of the officers who initiated the proposal for import of Black Matpe in November, 1987 jointly and the proposal was approved by the competent authority.

(c) Yes, Sir.

(d) The case of export of wheat bran has been investigated and the investigation report is under process by NCCF.

(e) There is no connectoin between the transfer of the Officer and the observations in the CAG's report.

Benefits of the Schemes for Removal of Unemployment and Poverty

2560. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the benefits of the schemes launched by Government for removal of unemployment and poverty have not reached the people for whom the schemes were intended;

(b) if so, whether Government have made any effort to ascertain the reasons therefor and modify them suitably;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the extent to which the schemes launched for removal of unemployment and poverty in Andhra Pradesh during 1984—88 have been successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) The concurrent evaluations studies undertaken on implementation of the poverty alleviation programmes like Integrated Rural Development Programme (IRDP) and National Rural Employment Programme (NREP) do not indicate such a dismal picture of performance under these programmes. IRDP evaluations indicate that about 60 per cent of the assisted families had crossed the poverty line of Rs. 3,500|- and 13 per cent of the families could cross the revised poverty line of Rs. 6,400|-. In 78 per cent cases the incremental income was generated by the assets provided under the programme. Similarly under NREP, the concurrent evaluations indicate about 79 per cent of the projects undertaken were found very useful and another 17 per cent somewhat useful. The evaluation studies do indicate some areas of concern in implementation of the programme. Corrective measures are introduced whenever monitoring mechanism throws up the need for it.

(d) In Andhra Pradesh, during the period 1984—88 families assisted under IRDP are 973,946 against the target of 873,409. Employment generated under NREP|RLEGP during this period against the target of 1024.26 lakh mandays and 894.31 lakh mandays, is 1037.77 lakh mandays and 1005.81 lakh mandays respectively.

वन उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण

2561. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी मांझी :

क्या कल्याण मंत्री 30 जुलाई, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 348 के दिए गए उत्तर को देखने और यह

बताने की कृपा करेंगे कि वन उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा बिचौलियों के शोषण से आदिवासियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : आदिवासी विकास व वन राज्य सचिवों तथा आदिवासी विकास सहकारी निगमों/वन विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के 23-24 जून, 1988 को हुए सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में ट्राइफेड ने, आदिवासियों को यथाशक्य ऊंचे दाम (जिन पर ट्राइफेड उनका माल उठाने पर राजी हो) दिलाने के उद्देश्य से प्रकीर्ण वन्य उत्पादों के विपणन में राज्य संघों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि बिचौलियों और आढ़तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण न हो सके। ट्राइफेड ने बहुत से प्रकीर्ण वन्य उत्पादों व कृषि उपज की जिंसों के अपने सामान क्रय-मूल्य निर्धारित किए हैं ।

2 संघ ने अपनी स्थापना के पहले वर्ष में जिन्स साल बीज, गोंद-कतीरा, हड़, नीजर बीज, बड़ी इलायची, रीठा, काजू व लाख एम एफ पी/एस ए पी की आठ जिंसों का व्यापार किया। ट्राइफेड द्वारा नियत ज्यादातर जिंसों के क्रय मूल्य गत वर्ष के मुकाबले ऊंचे थे ।

3 आदिवासियों को उनकी उपजों के उचित एवं पर्याप्त मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड, उपजों के विपणन में अपने कार्यकलापों में और तेजी ला रहा है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासियों से इमली व काजू मध्य प्रदेश सरकार को बिकवाने के लिए ट्राइफेड राज्य सरकार से बातचीत कर रहा है। ट्राइफेड ने चालू वर्ष में अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों से सरसों की सीधी खरीद की व्यवस्था की है ।

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्टस क्लब के शेड का तोड़ा जाना

2562. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्टस क्लब के उस शेड को तोड़ दिया है जो प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पूर्व बनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह शेड कब बनाया गया था और कितनी लागत पर, कितनी; और

(घ) क्या डेमोलीशन स्क्वाड ने हाल ही में बनी बहुउद्देशीय व्यायामशाला और मूल्यवान उपकरणों को तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को भी तोड़ दिया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने हाल में इस क्लब के लिए शौचालयों का निर्माण किया था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने कुछ अनधिकृत निर्माणों को गिराया है जो पार्क के उपयोग के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र पर निर्मित किए गए थे। तथापि, निर्माणों को गिराने के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी के कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1984 में 29705 रुपये की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित शेड को भी गिराया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को नष्ट नहीं किया गया परन्तु इसे पुनः स्थापना के लिए रखा गया है ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने किसी शौचालय का निर्माण नहीं किया है ।

2563. [*Transferred to the 30th March, 1989*]

Mandays Lost due to Strike and Lockouts

2564. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of mandays lost